



वदियुत मंत्रालय की वार्षिक समीक्षा (भाग एक)

चर्चा में क्यों?

भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 तक देश भर में 24x7 बजिली प्रदान करने के लिये बड़े पैमाने पर कार्यक्रम शुरू किया गया है। ग्रामीण वदियुतीकरण पर दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योतीयोजना (Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana - DDUGJY), शहरी वदियुतीकरण पर एकीकृत ऊर्जा विकास योजना (Integrated Power Development Scheme - IPDS) तथा मार्च 2019 तक सौभाग्य योजना (SAUBHAGYA scheme) के तहत अलग-अलग घरेलू वदियुतीकरण उपायों पर बल दिया जा रहा है।

महत्त्वपूर्ण बढि

- वर्ष भर भारत सरकार द्वारा थर्मल वदियुत उत्पादन (thermal power generation), पनबजिली और सबसे महत्त्वपूर्ण सौर, पवन और अन्य हरति ऊर्जा से संबंधित कई ऐतिहासिक निर्णय लिये गए हैं, इसके साथ ही प्रेषण और वतिरण को सुदृढ़ बनाने, फीडर को अलग करने और उपभोक्ताओं के लिये बजिली के मीटर व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- इसके तहत न सिर्फ क्षमता बढ़ाने की उपलब्धियाँ शामिल हैं, बल्कि विद्यमान बुनियादी ढाँचे में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने हेतु महत्त्वपूर्ण सुधारों को भी शामिल किया गया है।
- साथ ही, इसके अंतर्गत वदियुत के नुकसान को कम करने एवं उत्तरदायित्व और पारदर्शिता बढ़ाने के लिये कई मोबाइल एप्लिकेशन तथा वेबसाइटों जैसे- ऊर्जा एप, सौभाग्य पोर्टल, केन्द्रीय वदियुत पोर्टल, मेरिट पोर्टल की भी शुरुआत की गई।

मुख्य उपलब्धियाँ

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योतीयोजना (Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana - DDUGJY)

- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योतीयोजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत 32 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कुल 42,565 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

देश में ग्रामीण वदियुतीकरण की स्थिति

- संचयी रूप से (30 नवंबर, 2017 तक), 1,24,219 गाँवों में वदियुतीकरण और 4,68,827 गाँवों में गहन वदियुतीकरण का कार्य पूरा हो गया है।
- तकरीबन 277.20 लाख बीपीएल परिवारों को मुफ्त बजिली कनेक्शन जारी किया गए हैं।
- देश में 18,452 जनगणना गाँवों (2011 की जनगणना के अनुसार 5,97,644 के कुल ग्रामीण बस्तियों में से) में 1 अप्रैल, 2015 तक राज्यों द्वारा वदियुतीकृत नहीं किया गए थे।
- 30 नवंबर, 2017 तक, 15,183 गाँवों में वदियुतीकरण पूरा हो गया है। बचे हुए 2217 गाँवों में 1 मई, 2017 तक वदियुतीकरण होने की उम्मीद है।

सौभाग्य योजना (SAUBHAGYA : Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana)

- भारत सरकार द्वारा सितंबर 2017 में देश में सार्वभौमिक घरेलू वदियुतीकरण हासिल करने के लिये "प्रधानमंत्री सहज बजिली हर घर योजना (सौभाग्य)" नामक एक योजना की शुरुआत की गई,
- इस योजना की कुल लागत 16,320 करोड़ रुपए है, जिसमें 12,320 करोड़ रुपए का सकल बजटीय समर्थन शामिल है।
- इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी परिवारों को जोड़ना एवं बजिली कनेक्शन प्रदान करना है।
- ग्रामीण इलाकों में एसईसीसी आँकड़ों के आधार पर और शहरी इलाकों में आर्थिक रूप से गरीब परिवारों के आधार पर कम-से-कम वंचित रहने वाले सभी गैर-वदियुतीकृत परिवारों को मुफ्त बजिली के कनेक्शन दिये जाएंगे।
- इसके अलावा, दूसरे परिवारों से बलि के साथ दस समान कशितों में प्रतिपरिवार 500 रुपए का शुल्क लिया जाएगा।
- दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में स्थिति घरों को सौर फोटोवोल्टाइक (एसपीवी) आधारित सर्टिडअलोन पद्धति के साथ एलईडी लाइट, पंखे, पावर प्लग इत्यादि प्रदान किये जाएंगे।
- वर्ष 2011 के एसईसीसी आँकड़ों को आधार मानते हुए सामाजिक आर्थिक स्थितियों के अनुसार लाभार्थियों की पहचान की जाएगी।
- इस योजना के तहत 31 मार्च, 2019 तक सार्वभौमिक घरेलू वदियुतीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

एकीकृत ऊर्जा विकास योजना (Integrated Power Development Scheme - IPDS)

- आईपीडीएस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में गुणवत्ता और विश्वसनीय 24X7 नरिबाध बजिली आपूर्ति प्रदान करना है। अभी तक, नगिरानी समिति (Monitoring Committee) द्वारा 3,616 शहरों के लिये कुल 26,910 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। राज्यों से संबंधित संस्थाओं को 23,448 करोड़ रुपए मूल्य का कार्य दिया गया है।
- इस योजना में आईटी और तकनीकी सहायता के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में 24X7 बजिली की आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा, लेकिन बलिंग और संग्रहण दक्षता में भी सुधार करने में मदद मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप तकनीकी और वाणज्यिक (Aggregate Technical and Commercial - AT&C) नुकसान में भी कमी आएगी।
- अभी तक, आर-एपीडीआरपी (R-APDRP) के तहत 1363 शहरों को "गो-लाइव" (Go-Live) घोषित किया गया है, 52 शहरों में स्काडा नियंत्रण प्रणाली (SCADA control systems) की स्थापना की गई है, 20 स्काडा शहरों में कार्य पूरा कर लिया गया है
- इस योजना के भाग-1 के तहत 21 डेटा केंद्रों में से 20 अधिकृत हो चुके हैं तथा 970 शहरों में भाग-बी परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं।
- भारत में 45/57 डसिकॉम (नजी सहति) में उपभोक्ताओं के लिये ऑल इंडिया शॉर्ट कोड '1912' की शुरुआत हो चुकी है।

उज्ज्वल डसिकॉम एश्योरेंस योजना (Ujwal Discom Assurance Yojana - UDAY)

- 20.11.2015 को भारत सरकार द्वारा बजिली वितरण कंपनियों के वित्तीय और परिचालन को घाटे से उबार कर लाभ में लाने के लिये उज्ज्वल डसिकॉम एश्योरेंस योजना (उदय) को आरंभ किया गया।
- इस योजना का उद्देश्य लगभग 4.3 लाख करोड़ रुपयों के लंबे समय से करज और भविष्य में संभावित नुकसान का स्थायी समाधान करना है।
- इस योजना में सभी क्षेत्रों - उत्पादन, प्रेषण, वितरण, कोयला और ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने हेतु उपायों की परिकल्पना भी की गई है। योजना की वैधता अवधि दिनांक 31-03-2017 को समाप्त हो गई है।
- उदय के अंतर्गत प्रतभागी राज्यों के कार्य-प्रदर्शन की गहन नगिरानी सुनिश्चित करने हेतु एक अंतर-मंत्रालयी नगिरानी समिति कार्यप्रणाली (inter-ministerial Monitoring Committee Mechanism) स्थापित की गई है।
- अभी तक उदय योजना के अंतर्गत 27 राज्य और 4 संघ राज्य क्षेत्र शामिल हो चुके हैं।

प्रेषण (Transmission)

- "राष्ट्रीय वदियुत योजना [National Electricity Plan (Transmission)]" पर तैयार प्रारूप दस्तावेज़ 2021-22 की समय-सीमा में 226 गीगावॉट परियोजना की अधिकतम मांग को पूरा करने हेतु 2017-22 की योजनागत अवधि के लिये अंतर-क्षेत्रीय प्रेषण लकि सहति प्रेषण प्रणाली (प्रेषण लाइनों और संबद्ध सबस्टेशनों) को कवर करता है।
- सीबीटीई को सुविधाजनक बनाने हेतु पड़ोसी देशों को विशेष रूप से बजिली आपूर्ति के लिये उनकी प्रेषण प्रणाली को भारतीय उत्पादक केंद्रों से जोड़ा जा रहा है
- इस कार्य के लिये स्वतंत्र प्रेषण प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है, जिसके अनुमोदन के लिये सक्षम प्राधिकरण (Competent Authority) संबंधी आचरण व्यापार नियम (Conduct Business Rules - CBR) जारी किये गए हैं।

थर्मल (Thermal)

- पराली जलाने के कारण उत्पन्न प्रदूषण को कम करने के लिये, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा चूर्णित कोयले की आग से चालित बॉयलरों में को-फायरिंग के माध्यम से बजिली उत्पादन के लिये बायोमास उपयोग हेतु एक नीति जारी की गई है।

हाइड्रो पावर परियोजनाएँ (Hydro power projects)

- हाइड्रो पावर सेक्टर में, 1305 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाली 11 हाइड्रो पावर परियोजनाओं के वर्ष 2017-18 में चालू होने की संभावना है। इन परियोजनाओं में से, 465 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली 7 परियोजनाओं को 30.11.2017 तक पहले ही चालू कर दिया गया है और शेष को मार्च 2018 तक चालू करने की संभावना है।
- इसके अतिरिक्त 2880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (Dibang Multipurpose project) की डीपीआर को सीईए द्वारा वर्ष 2017 में मंजूरी प्रदान की गई है।